minimum wage is to be determined. We expect the Study Group to tell us on what basis it will be done, whether it will be on the basis of need-based or any other basis.

MR. SPEAKER: Next Question. (*Interruptions*) Don't record.

(*Interruptions*)**

SHRI H. M. PATEL: The question put by the hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta, is covered in the terms of reference. Whether it will be need-based or not is also a point which the Study Group has to consider.

MR. SPEAKER: Next Question. (*Interruptions*) Don't record.

(*Interruptions*)**

खाद्य तेलों की कमी

*728. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों की आगामी कुछ वर्षों में भी कमी बनी रहने की सम्भावना है ;

(ख) क्या आगामी पांच वर्षों में खाद्य तेलों का उत्पादन 20.12 लाख टन होने की संभावना है जब कि इनकी खपत 34.50 लाख टन होने का अनुमान है ; और

(ग) यदि हां, तो कमी को दूर करने तथा इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये तैयार की गई योजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) देश में खाद्य तिलहनों और तेलों के उत्पादन के उस समय तक मांग से कम बने रहने की सम्भावना है, जब तक तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये उपाय फल देना आरम्भ न कर दें।

(ख) आशा है कि किये गये उपायों के फलस्वरूप 34 लाख मीटरी टन की वर्तमान वार्षिक अनुमानित खपत की तुलना में खाद्य तेलों का वार्षिक उत्पादन 23 से 26 लाख मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन स्तर से अधिक होगा ।

(ग) वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये खाद्य तेलों का आयात उदारतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अलावा, किसानों को प्रोत्साहन देकर खाद्य तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय तैयार किये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं--

(1) सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में सुधरी टैक्नालाजी का तेजी से विस्तार करके प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना।

(2) नयी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में उपलब्ध संभाव्यता का उपयोग करके सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

(3) शुद्ध बीजों की आपूर्ति बढ़ाकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत करना।

(4) पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना। इसके लिये विशेष रूप से, जहां सम्भव हो बहुत बड़े इलाके में हवाई छिड़काव करना।

(5) समर्थन मूल्य निर्धारित करना तथा उन मूल्यों पर उपज खरीदने के लिये प्रबंध करना।

(6) कृषि विभाग के गहन तिलहन विकास कार्यक्रमों और अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणीकृत बीजों

**Not recorded

को लागत तथा पौध संरक्षण के विभिन्न कार्यों के लिये आर्थिक सहायता देना।

(7) सूर्यमुखी तथा सोयाबीन जैसी गैर-परम्परागत तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का बढ़ाना।

(8) आधुनिक निष्कर्षण तरीकों द्वारा तेलों का उत्पादन बढ़ाना।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि लगभग 10 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेलों की कमी रहने की सम्भावना है और उस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ उपाय भी बताये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि, जैसा उन्होंने अपने उत्तर के (ख) में कहा है "आशा है कि किये गये उपायों के फलस्वरूप 34 लाख मीटरी टन की वर्तमान वार्षिक अनुमानित खपत की तुलना में खाद्य तेलों का वार्षिक उत्पादन 23 से 26 लाख मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन स्तर से अधिक होगा।" तो इस आधार पर कमी या गैप तो रहेगा जो आपने स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन तेलों का आयात किया जा रहा है अथवा इस वर्ष कितना किया जायगा और इस वर्ष कितनी कमी रहने की सम्भावना है?

आपने जैसा कि प्रश्न के उत्तर के (ग) भाग के (5) में कहा है कि "समर्थन मूल्य निर्धारित करना तथा उन मूल्यों पर उपज खरीदने के लिये प्रबन्ध करना" तो आपने किन-किन वस्तुओं के बारे में अथवा प्रमुख सोयाबीन, सूर्यमुखी, ग्राउन्ड नट या मूंगफली इनका समर्थन मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया है? तथा निर्धारित मूल्यों पर उपज खरीदने के लिये कहां-कहां क्या प्रबन्ध किया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि पार साल जो आयल ईयर था 1976–77 उसमें डिमान्ड थी 32 लाख टन उसके अगेन्स्ट प्रोडक्शन था 24 लाख टन। इस प्रकार 8 लाख टन की कमी थी जिसको कि एस०टी०सी० के द्वारा और प्राइवेट ट्रेड के द्वारा पूरा किया गया। इस साल अध्यक्ष महोदय 1977–78 आयल ईयर के अन्दर जो प्रोडक्शन ऐस्टीमेटेड है वह 24.50 लाख टन है और उसके अगेन्स्ट डिमान्ड 34 लाख टन है। इस प्रकार जो गैप है वह लगभग साढ़े 9 लाख टन का है। इस गैप को भारत सरकार इम्पोर्ट के द्वारा पूरा कर रही है जिसमें 7 लाख टन इम्पोर्टेड आयल एस० टी० सी० के माध्यम से इम्पोर्ट किया जाता है और लगभग इसमें से 5 लाख लाख टन हमारी वनस्पती इंडस्ट्री को दिया जायगा और 2 लाख टन जो आयल है वह डायरेक्ट कन्ज़म्पशन के लिये वितरित किया जायगा। और अभी तक जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं इसी आयल ईयर के अन्दर 2 लाख 33 हजार 335 टन तेल आयात कर चुकी हैं। जहां तक मेरे मित्र का सम्बन्ध है, उन्होंने सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा, तो मैं आपके माध्यम से उनको और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि.... देश के अन्दर किसी भी प्रकार से तेल की कमी नहीं आने दी जायेगी और हम देखेंगे कि दाम विशेषकर नहीं बढ़ेंगे।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि सपोर्ट प्राईस हमने किस किस चीज की तय की है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि ग्राउंड-नट 160 रुपये, सोयाबीन 145 रुपये, सन फ्लावर 165 रुपये और तरसों के बीज के लिये 225 रुपये प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राइस घोषित की गई है और इस सपोर्ट प्राइस पर पर्चेज करने के लिए नाफेड को अथौराइज किया गया है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या यह सही है कि नाफेड द्वारा केवल पंजाब, हरियाणा और गुजरात में जाकर खरीद का कार्य किया जा रहा है, अन्य राज्यों में किसी प्रकार की खरीद का कार्य समर्थित मूल्य पर नहीं किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर

मूंगफली और सोयाबीन को बहुतायत होती है, क्या वहां भी नाफेड जाकर समर्थित मूल्य पर इन्हें खरीद करेगी ? सरसों के बारे में जो समर्थित मूल्य तय किया गया है, उसके बावजूद भी तेल की कीमतें निरन्तर बढ़ रही है, सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, मैं समझता हूं कि वह गलत आधार पर है। सरकार ने अभी तक जो सपोर्ट-प्राइस आयल सीड्स के लिए घोषित की है, चाहे मूंगफली हो, सोयाबीन हो या सरसों हो उसके बारे में किसी भी स्थान से ऐसी सूचना नहीं आई है कि इनका मूल्य सपोर्ट प्राइस से नीचे गया हो। कोई भी राज्य या स्थान ऐसा नहीं रहेगा जहां कि सपोर्ट प्राइस से मूल्य नीचे जायें। इसके बचाव के लिए नाफेड प्रबन्ध करेगा।

SHRI HITENDRA DESAI: When the rise in the price of oil has broken all records, I would like to know, whether Government would arrange for the distribution of oil at cheaper rates through fair price shops.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मेरे वरिष्ठ मंत्री श्री धारिया जी ने घोषणा की थी कि मस्टर्ड आयल का सब्स्टीच्यूट रेपसीड आयल है, इस रेप-सीड आयल को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले आरम्भ में इसका प्राइस साढ़े 8 रुपए किलो था, बाद में इसे साढ़े 7 रुपए किया गया। अब श्री धारिया जी ने सरकार की ओर से घोषणा की है कि यह 1 मई 1978 से सारे हिन्दुस्तान में हर कोने पर 7 रुपए किलो के भाव पर उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री मुल्तान सिंह चौधरी : जब गेहूं और धान की पैदावार बढ़ गई तो तेल की चीजों की पैदावार क्यों कम हुई ? उसका कारण यह है कि तेल की चीजों का दाम आधा भी नहीं मिलता है इसलिए किसानों ने फसल बोना छोड़ दिया। आपने सरसों की सपोर्ट प्राइस 225 रुपए रखी है, जब तक 400 रुपए नहीं रखेंगे, तब तक तेल नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं और गन्ने के पैसे अच्छे मिलते हैं तो उसको लोग ज्यादा बोते हैं। सरकार की नीति जो चल रही है, उसके मुताबिक 70 अरब रुपए का गेहूं बाहर से मंगाया गया, अगर यह रुपया यहां दिया जाता तो यहां फसल और अच्छी हो जाती क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि तेल की चीजों के पैसे कम-से-कम दुगने करें ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट की कास्ट पर कभी भी देश में इम्पोर्ट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। जो सपोर्ट प्राइस तय की है, वह सरकार ने स्वयं तय नहीं की है, बल्कि एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन के माध्यम से सब बातों पर विचार करने के बाद जितने आयल सीड्स की प्राइसिज तय की गई है, वे बिल्कुल ठीक हैं। आज के आयल सीड्स के भाव, खास तौर से मस्टर्ड सीड्स के भाव, जिस की सपोर्ट प्राइस सरकार ने 225 रुपए प्रति क्विंटल दी है, बिल्कुल वाजिब हैं।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Allegations regarding Affairs in the United Commercial Bank

*720. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether during late February, 1978 he has received several letters from Members of Parliament containing allegations regarding affairs in the United Commercial Bank Limited against the management of the Bank;

(b) if so, what are the allegations; and

(c) what action do the Government propose to take to investigate into the allegations ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Broadly speaking, the allegations include excess expenditure and irregularities in the sanction of loans and in the promotions/appointments in the bank.